

Delhi? The home of the drug industry is the West-coast particularly Gujarat and Maharashtra; but why is the giant Indian Drugs and Pharmaceuticals choose Delhi as its base?

The borders are hundreds of miles away yet the Border Roads Organisation is based in Delhi. The Farakka Barrage is at Farakka in West Bengal, yet the Farakka Barrage Control Board is in Delhi. It is perhaps ironic that even the Directorate of Lighthouses and Lightships is centered in Delhi, even though the nearest lighthouse is at least one thousand miles away.

The various units of the Education Ministry that are clustered in Delhi now can easily be moved away to other centres. Similarly, there are too many units of the Defence, Industries and Energy Ministry bunched in the city which can easily be spaced out in other centres like Bhopal, Gwalior, Indore, etc.

I suggest that the Planning Ministry set up an inter-ministerial working group to find way for deciding which of the government offices and Public Sector Undertakings offices be moved out from Delhi immediately and that there be a moratorium on the number of Central Government, Public Undertakings and State Government employees in Delhi. I urge this to be treated as a national problem.

(ii) ALLEGED POSTPONEMENT OF INDUCTION TRAINING PROGRAMME IN RESERVE BANK OF INDIA.

*SHRI CHINTAMANI JENA (Balosore): Two hundred bright young men and women selected for various Reserve Bank of India Officers posts have been rendered jobless due to the postponement of induction, training programme for an indefinite period. In January 1981 the RBI notified 200 vacancies of Grade 'A' Officers with starting emoluments of more than Rs. 2000/- a month. Written test and interviews were conducted in April and

August this year. Out of thousands of applicants who appeared in the test, 200 were finally selected by RBI Services Board in January 1982. The selected candidates were asked to resign their existing position and attend the medical examination held in March 1982 by RBI. They were advised to be ready to join their new assignment. Accordingly, they resigned the posts they were holding. In some cases these involve compensatory payments upto Rs. 10,000/- to the employers as they had signed bonds before they had joined those jobs. While the candidates were getting ready to report at RBI Staff Training College, Madras for the induction training programme they were informed that the programme had been deferred. Two months have elapsed since then but no intimation has been given to the candidates about their future prospects. Until yesterday most of those 200 young men and women were holding lucrative jobs. Now, their future is hanging in uncertainty. They are in great difficulties as they had resigned from their original posts to enable themselves to join in their new assignment with RBI.

In view of this, I draw the attention of the Government to take immediate steps to appoint and regularise them in the posts for which they were selected.

(iii) DISTRIBUTION OF MAHI RIVER WATER BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान व गुजरात सरकारों के मध्य सन् 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडारना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रांत के खेड़े जिले को सिंचित करने के लिए लिया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

के बाद में खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी कड़ाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सबसे सूखे इलाके बाड़मेर एवं जालौर में काम आएगा।

गुजरात ने सन् 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की श्रवहेलना करके खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित करके माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की कार्यवाही सन् 1966 में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने की माही ही एकमात्र कम खर्चे में पानी पहुँचाने का उपाय है, परन्तु गुजरात द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उससे राजस्थान प्रांत के और विशेषतः बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असंतोष है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुँचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊँचाई का कडारना बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी भाग डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था।

राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में दिनांक 24-12-80 को तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री राव बीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई थी।

उक्त बैठक में एक समिति का गठन केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। जिस में दोनों राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को सम्मिलित किया गया था, ताकि दोनों राज्यों के दावों का अवलोकन किया जा सके और माही नदी के पानी का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर व जालौर में किया जा सके।

गुजरात सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने में विलम्ब किया जा रहा है जबकि दोनों राज्यों के बीच में स्पष्ट समझौता हो चुका है।

यह प्रश्न राजस्थान प्रांत के विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को सिंचाई मंत्री एवं प्रधान मंत्री विशेष दिलचस्पी लेकर शीघ्र से शीघ्र निर्णय कराकर राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी अफ़ाल पीड़ित बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुँचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कराकर हरा-भरा करने में सक्रिय कदम उठाए।

(iv) UNSATISFACTORY TELEPHONE SERVICE IN JODHPUR.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में टेलीफोन व्यवस्था बहुत ही अस्त-व्यस्त हो गई है। टेलीफोन उपभोक्ता टुककाल करना तो दूर स्थानीय काल से भी बात नहीं कर पाते। डायल टोन 15-20 मिनट तक नहीं मिलना आम बात है एवं मिल जाने पर भी वांछित नंबर से बात नहीं हो पाती है। पिछले तीन वर्ष से लगातार यही